

असाधारण

### EXTRAORDINARY

भाग II---खण्ड 3----उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

## PUBLISHED BY AUTHORITY

**सं∘ 219**]

चई दिल्ली, मंगलवार, ग्रागैल 25, 1972, वैशाख 5, 1894

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 25, 1972/VAISAKHA 5, 1894

इस भाग में भिन्न पुष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके। Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

#### MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION

(Department of Labour and Employment)

ORDERS

New Delhi, the 25th April 1972

S.O. 313(E).—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Pyrites Phosphates and Chemicals Limited, Post Office Khandela, District Sikar and their workmen in respect of the matters specified in the Schedulc hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal with Shri Mohammed Yaqub Khan as Presiding Officer with headquarters at Jaipur and refers the said dispute for adjudication to the said Industrial Tribunal.

SCHEDULE

Whether the demands of the Khan Workers Union Saladipura, Khandela relating to (i) payment of Dearness Allowance, (ii) payment of 25 per cent Project Allowance to all the workmen, (iii) grant of 12 days casual leave in a year, (iv) grant of 10 days sick leave to all the mine workers and (v) payment of Washing Allowance to all the underground workmen are justified? If so, to what relief the said workmen are entitled?"

[No. L-29011/12/72-LR-IV.]

# श्रम ग्रीर पुनर्वास मंत्रः लयः (श्रम ग्रीर रोजगार विभाग)

श्रादेश-

नई दिल्ली, 25 श्रप्रैल, 1972

कां गां 313(ग्र).--धतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपावट अनुसूचीः में विनिद्धित विषयों के बारे में पाईराइट्स फास्फटस एण्ड केमिकल्स लिमिटेंड, डाक्यर, खान डेला, जिला सीकर के प्रवन्ध से सम्बद्ध नियोर्जकों और उनक कर्मकारों के बीच एक श्रीयोगिक विवाद विद्यमान है।

भीर यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायानिर्णयन के लिए निदक्षिक करना वांछनीय समझती है;

श्रतः, श्रव, श्रीधोगिक विवाद श्रिधिनियम, 1947 (1947 का 14) की झारा प्रक श्रीराधारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शिवतयों का प्रयोग करतें हुए, किन्दीक सरकार एतद्वारा एक श्रीद्योगिक श्रिधकरण गठित करती है जिसक पीठासीन श्रीधकारी और मोहम्मद याकूब खां, होंगे, जिनका भुस्यालय जयपुर होगा श्रीर उक्त विवाद को इक्ट श्रीद्योगिक श्रिधकरण को न्यायानिर्णयन क लिए निर्देशित करती है।

## ग्रनुसूची ं

"क्या खान कर्मकार संघ, सालादीपूरा, खानडेला की (i) महमाई असे के पूर-तान, (ii) सभी कर्मकारों को 25 प्रतिकात प्रयोजना भन्ते के सुमछान, (iii) वर्ष में 12 दिन श्राकस्मिक छुट्टी देने, (iv) सभी खानें कर्मकारों को 10 दिन की बीमारी छुट्टी देने श्रीर (v) भूमि के नीचे काम करने वाले सभी कर्मकारों को धुलाई भत्ता देने की मांगे न्यायोचित हैं? यदि हां, तो उक्त कर्मकार किस श्रमुतोप के हकदार हैं?"

[सं० एल-29011/12/72-एल-**मार० TV]** 

S.O. 314(E).—Whereas by an Order of the Government of India in the Winistry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. L-29011/12/72-LR-IV, dated the 25th April, 1972, an industrial dispute between the management of Pyrites Phosphates and Chemicals Limited, Post Office Khandela, District Sikar and their workmen has been referred to the Industrial Tribunal, Jaipur for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby prohibits the continuance of the strike in existence in the said establishments in connection with the said dispute.

[No. L-29011/12/72-LIR-IV.] KARNAIL SINGH, Under Sect.

का॰ आ॰ 314(आ).—यतः भारत सरकार के श्रम श्रौर पुनर्वास मंत्रालय (श्रम श्रौर रोजगार विभाग) के श्रादेण सख्या एल-29011/12/72—एल॰ ग्रार०—ः, तारीख 25 ग्रुप्रैल, 1972 द्वारा पाईराट्स फास्फट एण्ड केमिकल्स लिमिटेड, डाकघर खानडेला, जिला सीकर के प्रबन्ध से सम्बद्ध नियोजकों श्रौर उनके कर्मकारों की बीच विद्यमान श्रौद्योगिक विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए श्रौद्योगिक श्रीधकरण, जयपुर को निर्देणित किया गया है;

श्रतः, श्रवं, श्रौद्योगिक विवाद श्रिधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त प्रतिण्ठानों में उक्त विवाद के मिलमिल में विद्यमान हड़ताल के जारी रखे जाने का प्रतिषध करती है।

[सं० एल-29011/12/72—एल० घार - 4]° करनैल मिह, ध्रवरसचिय ।